(ख) और (ग) भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास, विशेष रूप में ग्रामीण जनता के लिए महत्वपूर्ण योगदान करने में सक्षम सिद्ध हुआ है। यह कार्य दो प्रचालनात्मक अन्तरिक्ष प्रणालियों अर्थात् प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध के लिए मुख्य रूप में भारतीय सुदूर संवेदन (उपग्रह आई०आर०एस०ए) प्रणाली तथा संचार, प्रसारण, दूरदर्शन सेवाएं, ग्रामीण टेलीग्राफी, मौसम विज्ञान, दूरवर्ती शिक्षा इत्यादि के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इनसेट) प्रणाली की सहायता से सिद्ध हुआ है।

देश में 24 राज्यों में स्थापित राज्य सुदूर संवेदन केन्द्र विविध कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए संबंधित राज्यों के संबद्ध विभागों एजेंसियों के साथ प्रभावी रूप में समन्वय कर रहे हैं।

अन्तरिक्ष विभाग द्वारा देश के 174 ज़िलों में सुदूर संवेदन आंकड़ों का उपयोग करते हुए भौगोलिक सूचना प्रणाली की सहायता से स्थानिक विशिष्ट विकास के लिए "दीर्घकालीन विकास के लिए समेकित मिशन" नामक एक प्रमुख परियोजना निष्पादित की जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्ध से संबंधित अनेक उपयोगों, जो ग्रामीण विकास से संबद्ध हैं- जैसे फसल के एकड़वार क्षेत्रफल और पैदावार के अनुमान, परती भूमि अभिनिर्धारण और उपयोगी बनाना, भूमिजल के संभावित क्षेत्रों का अभिनिर्धारण, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का मानचित्रण और क्षति का आकलन, सूखा मानीटरन, कमाण्ड क्षेत्र का प्रबन्ध, क्षारीय/लवणीय मृदाओं का मानचित्रण पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन इत्यादि के लिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का सामान्य रूप में उपयोग किया जा रहा है। उपग्रह संचार के क्षेत्र में ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यकर्ताओं इत्यादि को प्रशिक्षण और विकासात्मक संचार प्रदान करने के लिए इन्सेट का प्रयोग किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए इन्सेट पर एक प्रशिक्षण विकास संचार (टी०डी०सी०) चैनल को विशेष रूप में आवंटित किया गया है। पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों, जलविभाजक विकास कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, प्राइमरी शिक्षकों, महिला और बाल कल्याण कार्यकर्ताओं, सहकारिता के सदस्यों इत्यादि को प्रशिक्षण देने के लिए गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक गहन उपग्रह आधारित ग्रामीण विकासात्मक संचार और प्रशिक्षण परियोजना आयोजित की जा रही है। यह सांगोपांग परियोजना जिले में विकासात्मक क्रियाकलापों को संचार सहायता तथा फील्ड अधिकारियों को और समान्य रूप में जनता को अन्योन्यक्रियाशील प्रशिक्षण प्रदान करेगी। जिन विकासात्मक क्रियाकलापों के क्षेत्रों में संचार सहायता प्रदान की जायेगी, उनमें जल विभाजक प्रबन्धक, स्वास्थ्य, शिक्षा और पंचायती राज शामिल हैं। यह पाइलट परियोजना दो वर्षों की अवधि के लिए है तथा 1996 की अन्तिम तिमाही में शुरू होने वाली है तथा इससे प्राप्त अनुभव के आधार पर देश के अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार/संवर्धन किया जा सकता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, सुदूर संवेदन और उपग्रह संचार के क्षेत्रों में विकासात्मक क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने के लिए पांच उपग्रह, आई०आर०एस०-श्रृंखला में तीन उपग्रह तथा इन्सेट श्रृंखला में दो उपग्रह प्रमोचित किए जा चुके हैं।

National Memorial of Shri Morarjibhai Desai

1287. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have planned to establish a national memorial of late Prime Minister and a veteran Gandhian, Shri Morarjibhai Desai;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) how much amount is allotted for the project;

(d) whether a Committee has been formulated to administer the project; and

(e) whether the amount allocated to celebrate late Shri Morarjibhai Desai's Centenary has been diverted for this purpose; if so, what is the amount so diverted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) There is a proposal with the Government to establish a National Memorial of late Shri Morarji Bhai Desai.

(b) It is proposed to establish Morarji Desai Institute of Gandhian Studies to be located at Sabarmati, close to the place where Shri Desai was cremated. The Samadhi and the Institute would together constitute the Memorial to Shri Morarji Desai.

(c) No specific financial allocation has been made for this purpose so far.

(d) A concept Committee has since been constituted to develop a concept plan in this regard.

(e) Does not arise in view of (c) above.

Utilities of idle facilities of H.F.C. by L.O.C

1288. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Starred Questions 90 and 40 given in the Rajya Sabha on 6th March and 11th July, 1996, respectively, and state:

(a) whether any project report for utilising some of the idle facilities of H.F.C. at Haldia has been sent by Haldia Management of I.O.C.;

(b) what is the likely investment and the rate of return envisaged in the report; and

(c) by when a final decision is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS (SHRI T. R. BALU): (a) to (c) No such report has been received by Government from Indian Oil Corporation Limited.

Corruption and mis-utilisation of JRY funds

1289. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) what steps were taken in 1995-96 to reduce corruption and misutilisation of JRY funds;

(b) whether State Governments have been issued suitable directions in this regard;

(c) if so, whether proper implementation of the guidelines for JRY have been monitored in various States; and

(d) the record of Andhra Pradesh in implementation of JRY schemes in 1994-95 and 1995-96?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RUAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VARMA): (a) and (b) During 1995-96 instructions were issued to all State Governments to constitute vigilance and monitoring committees at the State, district and block level to supervise the implementation of the rural development programme including Jawahar Rozgar Yojana (JRY).

(c) and (d) JRY is continuously monitored in all the States including Andhra Pradesh according to the prescribed JRY guidelines. The achievements of these programmes during 1994-95 and 1995-96 are as under:—

Year	Achievement	
	Physical (lakh mandays)	Financial (Utilisation Rs. in crore)
1994-95	812.25	362.64
1995-96	701.57	345.57

Weeding out corrupt heads of PSUs

1290. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: SHRI GHUFRAN AZAM:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the National Confederation of Officer's Association of Central Public Sector Undertaking has urged Government to weed out those heads of PSUs who are corrupt in dealings;

(b) if so, whether Government have received any representations about corrupt heads of PSUs;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the action contemplated by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) to (d) According to a Resolution adopted recently by the National Executive Committee of the National Confederation of Officer's Association of Central Public Sector Undertakings, the confederation has urged the Government in a general way to weed out those chairman and Directors of PSUs, who are well known for their corrupt dealings. The matter is under examination.